- (c) if so, the number of houses that the State Governments propose to build during 1980-81 and the Central assistance sought and the decision of the Planning Commission taken in this regard; and
- (d) the allocation sought and those sanctioned by the Centre for Rajasthan and Madhya Pradesh respectively?

THE MINISTER OF PARLIA-MENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir. Housing is a State subject. Central financial assistance is given in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or head of development. The role of Central Government is mainly promotional and is limited to issuing of policy guidelines in respect of housing.

(b) to (d). Do not arise.

## पमुख टेर्स, फोन एक्सचेजों में टेली-फोन लाइनों में खराबियां

985. श्री विलास मुक्तेमवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) जुलाई, ग्रगस्त तथा सितम्बर, महीनों के दौरान प्रमुख टेलीफोन एक्स-चेंजों में सैकड़ों टेलीफोन लाइनों के कई कई सप्ताह तक खराब रहने के क्या कारण हैं; ग्रौर
- (ख) संचार की इस प्रणाली में बुटियों का जिनके का ज व्यापार, उद्योग तथा देश की ग्रन्य म त्वरूर्ण गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है शी घता से दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा है हैं?

संचार मंत्रास्तय में राज्य मंत्री (धी कार्तिक उराव): (क) यह सच है कि मानसून के महीनों, प्रथात् जुलाई, प्रगस्त, सितम्बर के दौरान प्रन्य समय की प्रयेक्षा मुख्यतया केबुल की खराबी के कारण प्रधिक टेलीफोन प्रभावित होते हैं। दोष-पूर्ण केबुलों की मरम्मत में प्रम्य खराबियों की ग्रपेक्षा ग्रधिक समय लगता है। सामान्यतः मानसून के दौरान प्रथात् जुलाई, ग्रगस्त भीर सितम्बर के महीनों में प्रभावित टेलीफोनों ग्रीर केबुल में उत्पन्न खराबियों को ठीक करने में कुछ सप्ताह लग जाते हैं।

यद्यपि भूमिगत केबुलों को सीसे के स्रावरण, स्टील टेप और वानिंग ट्रिक्स की स्थापना करके रक्षा की जाती है। फिर भी विभिन्न सेवामों की उपलब्ध कराने में संलग्न स्रन्य नागरिक प्राधिकारियों के खुदाई प्रचालनों से इनमें टूट-फूट हो जाती है। ये टूट फूट शुष्क मौसम में ध्यान में नहीं भाती और इसके दोष केवल उस समय दिखाई पड़ते हैं जब वर्षा के मौसम में केबुल में नमी दाखिल होती है। इसलिए मानसून के भारम्भ होते ही एकाएक अधिक संख्या में दोष प्रकट हो जाते हैं। इन दोषों के स्थान का पता लगाने और इनको ठीक करने में समय लगता है।

- (ख) केबुलों के खराब होने के कारण सामने आई समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा रहे हैं।
  - (1) शुष्क हवा द्वारा मृख्य केबुलों का दाबीकरण।
  - (2) जैली भरे वितरण केबुलों का प्रयोग ।
  - (3) टूट फूट से बचाने के लिए ग्रार सी सी नलियों में केबुल बिछाना।

- (4) केबुल मार्गों की प्रभावशाली देख-भाल।
- (5) दिल्ली में मिंगनसून के दौरान केंबुल में दोष उत्पन्न होने की सम-स्याग्रों से निपटने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया है।

## Permanent Machinery for Fixing up Procurement Price of Wheat and Paddy

986. SHRI VILAS MUTTEMWAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether Government propose to set up some permanent machinery for fixing up reasonable procurement prices of wheat and paddy in the various States of the country keeping in view the controversy which is raised on the recommendations of the Agricultural Prices Commission?

THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN) The Agricultural Prices Commission is a permanent body set up to advise the Government on the price policy for different agricultural commodities including wheat and paddy. Under its terms of reference, the Commission is enjoined to make its recommendations on the price policy for different agricultural commodities with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the over all needs of the economy and with due regard to the interests of the producer and the consumer. Before finalishing its recommendations, the Commission holds discussions with representatives of Central and State Governments, producers of agricultural commodities concerned, public sector agencies and other interests.

The recommendations of the Agricultural Prices Commission in respect of wheat, paddy, etc., are discussed with the States before a final decision is taken by the Government on the level of support procurement prices. In view of the requirement to evolve a balanced and integrated price structure the Government do not consider it desirable, or feasible, to fix procurement prices for wheat and paddy separately for each State.

## Buffer Stock and Off take of Foodgrains

987. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) the Central buffer stock of foodgrains as at the end of December, 1977, December, 1978, December, 1979, September, 1980; and
- (b) the total off take of foodgrains through the public distribution system year-wise from 1977-78, 1978-79, 1979-80 and 1980-81 (upto October, 1980)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) The total Central stocks of foodgrains with public agencies as at the end of December, 1977, 19778, 1979 and September, 1980 was as under:—

(in 'ooo Tonnes

•					
End.	December,	1977	٠	٠	13913
End.	Do.	1978	•	•	13928
End.	Do.	1979		•	14537
End.	Septemberl,	1980		•	8356

(b) The total offtake of foodgrains through public distribution system (including issues under Food For